



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1188।
No. 1188।

नई दिल्ली, मंगलबार, अगस्त 19, 2008/श्रावण 28, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2008/SRAVANA 28, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2008

का.आ. 2068(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि सोकहित में ऐसा वरपेशित है कि भारतीय खाद्य नियम में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रतिष्ठि. 6 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

इति: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उप-खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उपयोग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आई.आर. (पी.एल.)]

एस. कृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2008

S.O. 2068(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Food Corporation of India (FCI) which is covered by item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)]

S. KRISHNAN, Addl. Secy.